प्रत्येक सोमवार को हल्द्वानी से प्रकाशित

Mkd iathdj.k la[;k&;w-,-@uuhrky&335@2017&2019

Tittle Code - UTTHIN05123

कुमाऊं जनसंदेश

o"k&1 vad&15 gY}kuh ¼uuhrky½ lkeokj 25 flrEcj ls 1 vDVwcj 2017 i"B & 8 eY; 2 #i;s

राज्य सहकारी बैंक बांटेगा इस वर्ष 1453 करोड़ का लोन

बैंक की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में आर्थिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया

gY}kuhA राज्य सहकारी बैंक की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में अब तक की उपलब्धियों व आर्थिक स्थिति परर चर्चा के साथ ही बैंक को और उन्नति की ओर ले जाने पर चर्चा की गई। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 1453 करोड़ का लोन बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निकाय की बैठक हल्द्वानी के एक बैकेट हॉल में आयोजित की गई। विधिवत शुभारंभ के बाद राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और बैंकिंग के नए प्रयोगों को व्यवहार रूप में लाया जा रहा है जिससे कि खाताधारकों को नई सुविााओं से वंचित न होना पड़े। इस दौरान पिछले वर्ष के संतुलन पत्र की पुष्टि व आडिट पत्र का अनुमोदन किया गया। बैठक में पूरे राज्य से आए बैंक के समिति पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैंक के प्रबंधन निदेशक दीपक कुमार ने बैंक का वार्षिक लेखाजोखा प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रबंधक निदेशक प्रमोद कुमार, जिला सहकारी बैंक नैनीताल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, विधायक लाल कुआं नवीन दुम्का संचालक , किरन नेगी, मंजू बिष्ट, बर्फी भक्ति, हयात सिंह मेहरा, मानवेंद्र सिंह, धनश्याम नौटियाल, देवेंद्र कुमार, सुरेन्द्र सिंह, उप निबंधक सहकारिता एमपी त्रिपाठी, जिला सहायक निबंधक डीडी गुरुरानी, जिला सहकारी बैंक नैनीताल के महाप्रबंधक सीके कमल व उधमसिंह नगर सहकारी बैंक अध्यक्ष पीसी दुम्का , महाप्रबंधक एनपीएस ढाका, महाप्रबंधक धर्मवीर सिंह, बैंक संचालक राजेन्द रावत, श्रम निर्माण संघ अध्यक्ष राजकुमार नेगी, सचिव शिव बहादुर सिंह, चंदन सिंह नेगी , पंकज सुयाल सहित तमाम लोग मौजूद थे।

आठ से 13 अक्टूबर तक होगी सेना भर्ती

gY}kuhA कुमाऊं मण्डल के सेना भर्ती की व्यवस्थाओं के लिए आर्मी केन्ट हल्द्वानी में सेना व प्रशासनिक अधिकारियो की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। आठ अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होने वाली सेना भर्ती में प्रतिदिन 6 से 7 हजार अभ्यर्थियो की आने की सम्भावनायें को देखते हुये बैरिकेडिंग, पेयजल, विद्युत, सफाई, सुरक्षा व्यवस्थाओ को चुस्त दुरूस्त रखा जायेगा।

सेना भर्ती रैली में केन्ट एरिया के अन्दर मोबाइल व निजी वाहन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी दीपेन्द्र कुमार चाधरी ने रैली मे आने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल व निजी वाहन कतई न लायें। रात को 1 से 2 बजे सेना अभ्यर्थियों को बेरिकेडिंग के द्वारा लाइन बनाकर भर्ती स्थल में प्रवेश करने दिया जायेगा। इसके उपरान्त दो से ढाई सौ अभ्यर्थियों के समूह बनाकर उनके प्रमाण पत्रों की जांच शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कराकर दौड प्रारम्भ कराई जायेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की ओर से भर्ती रैली में चिकित्सा शिविर लगाया जायेगा। पेयजल व्यवस्था जल संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, साथ ही गेट के बाहर उचित प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था की जायेगी। 20 सचल शौचालय लगाये जायेगें, व बाहरी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रखने हेतु व्यापक मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जायेगा। उन्होने कहा कि विभिन्न जनपदों से आने वाले अभ्यर्थियों के यातायात हेतु रोडवेज एवं केएमओयू की बसें अतिरिक्त बसें लगाई जायेगी ताकि युवाओं को आने–जाने में अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पडे। उन्होने चेतावनी दी है कि प्राइवेट वाहनों द्वारा अधिक किराया वसूलने पर कडी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अनुशासन व शान्तिपूर्वक भर्ती रैली मे प्रतिभाग करें, व सभी अभियर्थी अपने साथ मूल अभिलेख अवश्य लायें। भर्ती अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि 8 अक्टूबर को जिला बागेश्वर, 9 अल्मोडा, 10 उधमसिह नगर ,11 नैनीताल, 12 पिथौरागढ व 13 अक्टूबर को चम्पावत जनपद के अभियर्थियों की भर्ती होगी। इसके बाद चयनित अभियर्थियों का चिकित्सा परीक्षण होगा। सैन्य अधिकारियो द्वारा बताया गया कि भर्ती रैली मे जो भी अधिकारी व कर्मचारी लगाये जायेंगे उन्हें आर्मी द्वारा परिचय पत्र जारी किये जायेंगे।

परिचय पत्र के बिना भर्ती स्थल पर प्रवेश नही कर पायेगे। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से कहा कि भर्ती लगाये जाने वाले कर्मचारियों की सूची मय फोटोग्राफ के साथ सैन्य अधिकारियो को उपलब्ध करा दें। बैठक मे कर्नल दिनेश नायर, कर्नल वीएस साई, अपर जिलाधिकारी हरवीर सिह, सिटी मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी एपी बाजपेयी,अधिशासी अभियन्ता लोनिवि आरएस रावत, जलसंस्थान एसके उपाध्याय, विद्युत डीके जोशी, एआरटीओ गुरदेव सिह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एमएम तिवारी के अलावा सैन्य अधिकारी मौजूद थे।

बेरोजगारी को लेकर लोग हमसे नाराज थे, पर मोदी भी विफलः राहुल

fçLVuA कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यहां कहा कि दुनिया में बेरोजगारी से लोग परेशान हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को लोगों ने चुना। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में इस समस्या के लिए पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर रहे हैं। गांधी यहां दो हफ्ते की अमेरिका यात्रा पर हैं। प्रिंस्टन यूनीवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत में गांधी ने स्वीकार किया कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को भारत में सत्ता इसलिए मिली क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी से बेरोजगारी के मुद्दे पर नाराज थे।उन्होंने कहा कि रोजगार का पूर्ण मतलब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लोगों को सशक्त करना और शामिल करना है। गांधी ने छात्रों से कहा, ''मैं सोचता हूं, मोदी के उभार का मुख्य कारण और ट्रंप के सत्ता में आने की वजह, अमेरिका और भारत में रोजगार का प्रश्न होना है। हमारी बड़ी आबादी के पास कोई नौकरी नहीं है और वह अपना भविष्य नहीं देख सकते हैं। और इसलिए वह परेशान हैं, और उन्होंने इस तरह के नेताओं को समर्थन दिया है।'' उन्होंने कहा कि एक अन्य समस्या यह है कि बेरोजगारी को कोई समस्या मान ही नहीं रहा है।

राहुल गांधी ने कहा, ''मैं ट्रंप को नहीं जानता। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन, निश्चित ही हमारे प्रधानमंत्री (रोजगार सृजन के लिए) पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं।'' गांधी ने अमेरिका में विशेषज्ञों, व्यापारिक नेताओं और कांग्रेस के सदस्यों के साथ अपनी बैठक में बेरोजगारी का मामला बार बार उठाया है। उन्होंने बर्कले में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को संबोधित करते हुए कहा था, ''इस समय हम पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर रहे हैं। हर दिन रोजगार बाजार में 30,000 नए युवा शामिल हो रहे हैं और इसके बावजूद सरकार प्रतिदिन केवल 500 नौकरियां पैदा कर रही है। इसमें बड़ी संख्या में पहले से ही बेरोजगार युवा शामिल नहीं हैं।''

गांधी ने यहां कहा कि भारत को चीन के साथ मुकाबला करने के लिए स्वयं में बदलाव करने की आवश्यकता है और इसके लिए देश के लोगों को रोजगार की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''हमारे (एक दिन में) 30,000 नौकरियां पैदा नहीं कर पाने से जो लोग हमसे नाराज थे वे श्री मोदी से भी नाराज होंगे। मुख्य प्रश्न इस समस्या को सुलझाना है। श्री मोदी के साथ मुख्य मसला यह है कि वे इस मुद्दे से ध्यान भटका देते हैं और यह कहने के बजाए कि सुनो हमें एक समस्या है, वह किसी ओर पर उंगली उठा देते हैं।'' राहुल ने कहा, ''भारत में इस समय लोगों में गुस्सा भर रहा है। हम इसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरे लिए चुनौती एक लोकतांत्रिक पर्यावरण में रोजगार सृजन की समस्या को सुलझाना है। यह चुनौती है।''उन्होंने तर्क दिया, ''इसके लिए पहले हमें स्वीकार करना होगा, कि यह एक समस्या है। इसके बाद हमें एकजुट होकर इससे निपटने की कोशिश करनी होगी। इस समय, कोई यह स्वीकार तक नहीं कर रहा कि यह एक समस्या है।'' राहुल ने प्रिंसटन में अपने अधिकतर प्रश्नोत्तर सत्र में रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि नई तकनीक एवं आध्ुनिकीकरण से रोजगार कम होने की संभावना नहीं है।

उन्होंने भारत में ध्रुवीकरण का मामला भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति भारत में मुख्य चुनौती है और अल्पसंख्यक समुदायों और जनजातीय लोगों समेत समाज के कुछ वर्गों को ऐसा नहीं लगता कि वे सत्तारूढ़ भाजपा की सोच का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, ''21वीं सदी में यदि आप कुछ लोगों को अपनी सोच से बाहर रख रहे हैं, तो आप संकट को बुला रहे हैं। नए विचार आएंगे, नई विभिन्न सोच विकसित होंगी। इसलिए, मेरे लिए भारत में मुख्य चुनौती ध्रुवीकरण की राजनीति है जहां आप एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर देते हैं और आप अन्य लोगों के आने के लिए जगह पैदा कर देते हैं।''

गांधी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ''10 करोड़ जनजातीय लोगों का एक इलाका है जो (भाजपा की) सोच को लेकर सहज महसूस नहीं करता। भारत में कई राज्य हैं, जो नहीं चाहते कि उन पर एक ही सोच लागू की जाए। देश में अल्पसंख्यक समुदाय है, उन्हें नहीं लगता कि वे इस सोच का हिस्सा है। असल खतरा यही है।'' उन्होंने कहा कि लोगों को गले लगाना ही भारत की ताकत रही है।

जी हां, चाय की चुस्कियां बना सकती हैं आपका कॅरियर भी!

भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनकी सुबह चाय की चुस्कियों के साथ ही होती है। एक कप बेहतरीन चाय उनका पूरा दिन बना देती है। वे चाय के स्वाद के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करते। जिसके कारण टी इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है। शायद आपको पता न हो लेकिन दुनिया में चाय का उत्पादन करने वाले देशों में भारत अग्रणी स्थान पर है। इतना ही नहीं, चाय की खपत में भी भारत सबसे आगे है। ऐसे में अगर आप भी चाय की चुस्कियां लेते हुए अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं तो बतौर टी टेस्टर अपना एक बेहतरीन भविष्य देख सकते हैं।

D;k gksrk gS dke

टी टेस्टर का मुख्य काम चाय का परीक्षण करना होता है। वह सिर्फ चाय को टेस्ट करके सिर्फ उसके स्वाद को ही नहीं पहचानता, बल्कि अन्य कंपनियों की चाय के स्वाद में अंतर भी बताता है। जब वह चाय के स्वाद का तुलनात्मक परीक्षण करता है तो अपनी कंपनी की चाय को बेहतर बनाने के हर संभव तरीकों का सुझाव भी पेश करता है। साथ ही वह लोगों की रूचि को ध्यान में रखते हुए चाय की चुस्कियों को बेहतर बनाने का हरसंभव प्रयास करता है।

fLdYl

इस क्षेत्र में भविष्य देख रहे छात्रों की स्वाद ग्रंथि व सुंगध पहचानने की क्षमता बेहतर होनी चाहिए। साथ ही आपका प्रकृति प्रेमी होना भी बेहद आवश्यक है। आपको चाय बागान में चाय उगाने और उसे तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए ताकि वह आवश्यक बदलाव करके संबंधित ब्रांड को अधिक बेहतर बना पाए। साथ ही उसे चाय बाजार और लोगों के टेस्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। तभी वह अपने ब्रांड व अपने कॅरियर को एक नई उंचाई दे पाएगा। इन सबके अतिरिक्त आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ व बारीक से बारीक बदलाव को भी पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए आपके वैज्ञानिक ज्ञान के अतिरिक्त प्रैक्टिस करना भी बेहद आवश्यक है तभी आप चाय के स्वाद को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे।

;kX;rk

यूं तो इस क्षेत्र में कोई प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी क्षमताओं, गुणों व वैज्ञानिक ज्ञान को निखारने के लिए आप संबंधित संस्थानों से डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आप फूड साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस या बॉटनी में शैक्षिक योग्यता प्राप्त करके भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं।

lHkkouk,a

टी टेस्टिंग का कॅरियर एक उभरता हुआ क्षेत्र है, इसलिए अभी तक लोगों को इसकी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। ऐसे में यहां पर जॉब की ढेरों संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे छात्र हॉस्पिटेलिटी और बड़े. बड़े होटलों में भी जॉब देख सकते हैं। वर्तमान में, फाइव स्टार होटलों में भी टी टेस्टर की डिमांड होती है। इसके अतिरिक्त टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो हमेशा ही एक स्पेशलाइज्ड टी टेस्टर की

अल्मोड़ा में इस बार जलाए जाएंगे 32 पुतले

जिलााधिकारी ने महोत्सव समिति पदाधिकारियों व अधिकारियों की बैठक में की चर्चा

ftyk lHkkxkj dk;ky; e cBd vk;kftr

vYekMkA दशहरा महोत्सव को शान्तिपूर्वक मनाये जाने हेतु जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज दशहरा मेला समिति के सदस्यों एवं राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक बैठक जिला कार्यालय के सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने दशहरा मेला समिति के सदस्यों को कहा कि नगर में पुतलों के निकलते समय प्रत्येक पुतले के सदस्यों को परिचय पत्र जारी करें ताकि महोत्सव में किसी प्रकार का व्यवधान एवं अशान्ति का माहौल न बनने पाये। उन्होंने कहा कि दशहरे के दिन शराब की दुकानें 1:00 बजे तक खुली रहेंगी और उसके बाद पूर्णतयः बन्द रहेंगी इस हेतु पुलिस प्रशासन एवं आबकारी विभाग को निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि यदि कही पर शराब बिकती हुई पायी जाती है तो शराब विक्रेताओं एवं शराब पीने के ऊपर पैनी नजर रखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय।

बैठक में अवगत कराया गया कि सभी पुतलें शिखर होटल के पास टैक्सी स्टैण्ट से चलना प्रारम्भ करेंगे तथा पुरानी व्यवस्था के अनुसार ये पुतलें लाला बाजार एवं मुख्य बाजार होते हुए आर्मी गेट से स्टेडियम पहुचेंगे इस दौरान मुख्य बाजार में किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जायेगी। उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को निदेश दिये कि वे एक पेयजल टैंकर टैक्सी स्टैण्ड एवं एक टैंकर स्टेडियम में उपलब्ध रखें। जिलाधिकारी ने मुख्य बाजार में टूटे पटालों, पेयजल पाईप लाइनों एवं गडढ़ों को दशहरे से पहले ठीक करने के निर्देश सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दिये।

जिलाधिकारी ने दशहरा महोत्सव को पर्यटन से जोड़ने के लिये इस महोत्सव की वीडियों एवं फोटोग्राफी कवरेज करने के निर्देश जिला पर्यटन अधिकारी को दिये। उन्होंने कहा कि दशहरा महोत्सव भव्य हो इस हेतु दशहरा महोत्सव समिति के सदस्यों एवं पुतला समिति के सदस्यों से इस महोत्सव को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रत्येक वर्ष बढ़ रहे पुतलों की संख्या पर कहा कि इनकी संख्या 20 से कम की जाय इस पर दशहरा समिति के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष 32 पुतले बनाये जायेंगे जिनका निरीक्षण दिनांक 29 सितम्बर को किया जायेगा मानक में जो पुतलें नहीं आयेंगे उन्हें अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि जो मानक लम्बाई, चौड़ाई व साज–सजा हेतु तय किये गये है उनमें जो पुतले मानक के अनुसार नहीं बने होंगे उनमें से 05 पुतलों को इस वर्ष हटा दिया जायेगा इसी तरह यह प्रक्रिया आगामी 02 वर्षों तक चलेंगी। दशहरा महोत्सव का प्रयास होगा की इनकी संख्या 2 दर्जन से कम हो सके।

जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नगर में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थिति ठीक रखें साथ ही जहां पर नव दुर्गा महोत्सव व रामलीलाओं को आयोजन हो रहा है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिये कि पुतलों को ले जाने वाले मार्ग की मरम्मत का कार्य समय से पूर्ण करे लें। इसके अलावा उपजिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक को निर्देश दिये कि वे दिनांक 26 सितम्बर को नगर में संयुक्त भ्रमण कर विद्युत केबिल, टेलीफोन व जल सस्थान की लाइनों का निरीक्षण कर लें ताकि पुतलों को ले जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने निर्देश दिये कि पुतलों की ऊँचाई 14 फीट से ज्यादा न हो इसका विशेष ध्यान रखें।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पुतलें दिन में 1:00 बजे तक निर्धारित स्थान पर पहुँच जायं इसका ध्यान आयोजकों को रखना होगा और इनका प्रस्थान 2:30 बजे अनिवार्य रूप से कराना भी सुनिश्चित करना होगा ताकि समय से पुतलें स्थानीय स्टेडियम में पहुँच सकें। स्थानीय स्टेडियम में सफाई की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जायेगी और दशहरा महोत्सव समिति उन्हें यथोचित मात्रा में बडे कूडेध्दान उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कि यहा के दशहरे की अपनी विशिष्ट पहचान हैं इसलिये इस कार्यक्रम को हमें आपसी समन्वय बनाकर सम्पन्न कराना होगा। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत व नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिये जहां–जहां पर उनके क्षेत्रान्तर्गत झाड़ियां हैं उनकी सफाई व एक अभियान चलाकर शीध्र कर दें क्योंकि अनेक स्थानों से बाघ आने की शिकायतें प्राप्त हो रहीं है और ग्रामीण लोग रामलीला को देखने आते है इसलिये इस कार्य को प्राथमिकता से किया जाय। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये जो क्षेत्र संवेदनशील है वहां पर पिंजरे की व्यवस्था करा दी जाय। इस बैठक में अनेक विभागों के अधिकारियों के समय पर न पहुंचने पर जिलाधिकारी नाराजगी व्यक्त की।

इस अवसर पर दशहरा समिति के अजीत कार्की, तुसार कान्त शाह, विनीत बिष्ट, कैलाश गुरूरानी, हरीश शाह सहित अन्य लोगों ने अपने सुझाव रखे और जिला प्रशासन को आश्वस्त किया कि जो भी व्यवस्थायें दशहरा महोत्सव समिति करेंगी उस वे जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को विश्वास में लेकर काम करेंगी।

इस अवसर पर सीडीओ जेएस नगन्याल, एडीएम केएस टोलिया, एसडीएमविवेक राय, पुलिस उपाधीक्षक आरएस टोलिया ने गत वर्षों के अनुभावों के आधार पर दशहरा समिति से अपील की कि प्रयास यह करना होगा कि सभी पुतलें निर्धारित समय सायं 08 बजे से पहले पहुंच जायं। इस अवसर पर आयोजित होने वाले आतिशबाजी के सम्बन्ध में भी विचार विर्मश हुआ। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम स्थल पर एक एम्बुलैंस, अग्निशमन वाहन व डाक्टरों की एक टीम खेल विभाग में उपलब्ध रहेंगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा. निशा पाण्डे, धर्मेन्द्र बिष्ट, राजेन्द्र तिवारी, सुशील शाह सहित दशहरा समिति के सभी सदस्य व अधिकारी मौजूद थे।

टीकाकरण अभियान का करें प्रचार : सीएमओ

#æi|jA भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशानुसार जनपद में 30 अक्टूबर से अभियान चलाकर मीजिल्स–रूबैला वैक्सीन के टीके 09 माह से 15 वर्ष तक के बच्चो को लगाये जाने है। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी आरके पाण्डे की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई।

मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि शत–प्रतिशत बच्चो को टीकाकरण से आच्छादित किया जा सके। उन्होने कहा इस कार्य मे जो आशा कार्यकर्ती, एएनएम व विद्यालय अच्छा कार्य करेंगे, उन्हे प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे। उन्होने बताया हमारे देश मे प्रतिवर्ष 15 वर्ष तक के बच्चे मीजिल्स एवं रूबैला से ग्रसित होते है जिसके कारण बच्चों मे डायरिया, निमोनिया एवं आंखों के रोग हो जाते हैं। कभी–कभी मीजिल्स–रूबैला के कारण बच्चो की मृत्यु भी हो जाती है।

उन्होने कहा सभी अभिभावक जागरूक होकर अपने बच्चो को मीजिल्स व रूबैला के अवश्य टीके लगाये ताकि बच्चों में होने वाले डायरिया, निमोनिया व आंखो के रोगो से निजात मिल सके। उन्होने कहा 05 तारीख को पोषण दिवस के अवसर पर सभी आंगनबाडी केन्द्रो मे इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार किया जाए। इस कार्यक्रम मे आंगनबाडी कार्यकर्तियो के साथ–साथ आशा व एएनएम भी प्रतिभाग करेंगे। उन्होने कहा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओ का भी सहयोग लिया जायेगा। बैठक मे विश्व स्वास्थ संगठन के मनु खन्ना द्वारा विस्तृत जानकारियां उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर डा. मनीष अग्रवाल, डा. अविनाश खन्ना, डीपीओ अखिलेश मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक गुसाई, अजय कुमार, महेश चन्द्र, एनके सक्सेना, चन्दर सिंह, अजय कुमार, पिताम्बर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

सम्पादकीय...

महिला आरक्षण का सवाल

बेशक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए सियासी चाल चली है। कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा करने की है। इसके बावजूद एनडीए सरकार को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। अगर सरकार संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान कर पाई, तो उसकी अनेक सफलताओं के बीच यह एक और अनुपम उपलब्धि होगी।

महिला आरक्षण विधेयक की विडंबना यह है कि इसके पक्ष में लगभग पूर्ण राजनीतिक सहमति के बावजूद यह बिल 21 साल से लटका है। इस दौरान केंद्र में विभिन्न् प्रमुख दलों की सरकार बनी। मगर किसी ने इसे पारित कराने में वास्तविक रुचि नहीं दिखाई। इस बीच सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने दस साल (2004–14) तक केंद्र में सरकार का नेतृत्व किया। उसने 2010 में राज्यसभा से महिला आरक्षण के लिए संविधान में 108वें संशोधन का विधेयक पास जरूर कराया, मगर लोकसभा में आते–आते उसका संकल्प जवाब दे गया। अब सोनिया ने उस समय उस सदन में उनकी पार्टी का अपना बहुमत न होने की आड़ ली है। और प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि वे लोकसभा में अपनी पार्टी के बहुमत का लाभ उठाते हुए ये बिल पारित कराएं। इसके बाद उन्होंने महिला उत्थान के प्रति कांग्रेस की निष्ठा का बखान यह कहते हुए किया कि उनकी पार्टी ने संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के जरिए पंचायतों व नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष से यह जरूर पूछा जा सकता है कि 2010 में उनकी पार्टी की सरकार ने जो इरादा राज्यसभा में दिखाया, वह लोकसभा में आकर क्यों कमजोर पड़ गया? तब भले कांग्रेस का अपना बहुमत नहीं था, किंतु भाजपा व वाम दलों सहित कई दूसरी पार्टियों का समर्थन बिल के साथ था।

बहरहाल, इस मुद्दे पर आरोप–प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है। इस साल के आरंभ में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा था कि बिना कोई विवाद किए इस बिल को सम्मानजनक तरीके से पास किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल अगर स्पीकर की भावना के मुताबिक आचरण करें, तो विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उद्देश्य अवश्य पूरा हो सकता है। गौरतलब है कि मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में सिर्फ 62 महिला सदस्य हैं। और ये सदस्य संख्या अब तक की उच्चतम है।

ट्रंप का कड़ा संदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने पहले भाषण में कई अहम पहलुओं की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। हालांकि उनकी खास शैली यहां भी ठीक वैसी ही तीखी प्रतिक्रियाओं का सबब बनी, जैसी वह अमेरिका के अंदरूनी मामलों में बनती आई है। उनका भाषण यूएन में अभी तक दिए गए सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के भाषण से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि विश्व एक अहम मोड़ पर खड़ा है। हम एक ऐसे समय में मिल रहे हैं जब उम्मीदें और खतरे, दोनों ही बहुत बड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय आतंक और आपराधिक नेटवर्क से खतरा बढ़ा है। वे निरंकुश सरकारें भी चुनौती पेश कर रही हैं जिनके पास जनसंहारक हथियार हैं। ट्रंप ने कहा कि हम चाहें तो दुनिया को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या उसे ऐसे गर्त में गिरा सकते हैं, जहां से उसे बचाया नहीं जा सकता। उन्होंने संकेत किया कि इन खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र का रोल महत्वपूर्ण है। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की बड़ी आलोचना की थी। ऐसे में यह उत्सुकता थी कि वह इसकी भूमिका को लेकर क्या कहेंगे। गनीमत है ट्रंप ने इसकी भूमिका को अहम माना है।

आर्थिक सुस्ती की फिक्र

बेशक हाल में कुछ आर्थिक संकेत ऐसे मिले, जिन्हें सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर का गिरकर 5.7 फीसदी तक चले जाना रहा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और चालू खाता घाटे के ताजा आंकड़े भी अच्छे नहीं रहे। जब ऐसी खबरें आती हैं, तो विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने के बहाने मिलते हैं। जाहिर है, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई है, जैसे कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया हो। विपक्ष ने इस कथित संकट के लिए केंद्र को दोषी ठहराया है। प्रचारित किया है कि एनडीए सरकार की नीतियां वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। खासकर नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के तरीके को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई है। मसलन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्यम एवं लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 40 फीसदी है। ये दोनों क्षेत्र नोटबंदी और जीएसटी के कथित दुष्प्रभावों से संकट में हैं। इसका असर जीडीपी वृद्धि दर पर दिख रहा है।

बहरहाल, ऐसी नकारात्मक तस्वीर पेश करने की कोशिश में अर्थव्यवस्था से जुड़े स्वस्थ एवं सकारात्मक संकेतों की उपेक्षा कर दी गई है। जबकि हकीकत यह है कि शेयर सूचकांक बेहद ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं, देश में रिकॉर्ड मात्रा में विदेशी मुद्रा आई है, डॉलर की तुलना में रुपया अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है, और हाल में निर्यात बढ़ने के संकेत भी मिले हैं। इन फौरी पहलुओं के अलावा अगर दीर्घकालिक सूरत पर गौर करें, तो भारत का आर्थिक भविष्य सहज ही उज्ज्वल नजर आता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यहां की युवा आबादी है। जनसंख्या का ये हिस्सा एक ऐसे बाजार का आधार है, जो लंबे समय तक अधिक उत्पादन, बिक्री और मुनाफे का स्रोत बना रहेगा। दरअसल, नोटबंदी और जीएसटी को लागू करके भी सरकार ने आर्थिक खुशहाली का आधार मजबूत किया है। जीएसटी से आगे चलकर कारोबार करना आसान होगा।

नोटबंदी से स्वच्छ अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे देशी–विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। यानी समग्रता में देखें तो मायूसी की कोई बात नजर नहीं आती। इसके बावजूद जहां कमजोरी दिख रही है, उसे दुरुस्त करने के कदम फौरन उठाए जाने चाहिए। संतोष की बात है कि केंद्र इसको लेकर जागरूक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि हालात पर सरकार की नजर है और आर्थिक स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में हैं। फिर भी सरकार से उम्मीद है कि वह ऐसे प्रभावी कदम उठाए, जिससे तात्कालिक चिंताओं का भी निवारण हो सके। तब विपक्ष की रणनीति निराधार हो जाएगी। सरकार को आम लोगों की दिक्कतों की चिंता अवश्य करनी चाहिए। अधिक टैक्स के कारण पेट्रोल–डीजल की महंगाई आम लोगों के बीच मुद्दा बन रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या आयकर व दूसरे करों में और कटौती संभव है, इस पर उसे विचार करना चाहिए। ऐसे कदमों से उपभोग बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में नई गति आ सकती है।

अभी से हो गर्मी की तैयारी

मध्यप्रदेश के 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश होने के कारण 23 विकास खंडों में पिछले साल की तुलना में भू–जलस्तर 5 मीटर से नीचे चला गया है। ऐसे में जनवरी से ही पेयजल संकट के आसार बनने लगे हैं। जल संसाधन विभाग के मुताबिक ऐसी स्थिति में गर्मी में पेयजल की उपलब्धता के लिए अभी से तैयारी होना चाहिए। विभाग के मुताबिक 145 विकास खंडों में भी भू–जलस्तर एक से तीन मीटर तक गिरा है। अगली गर्मी के संदर्भ में यह स्थिति खराब है। केवल 27 विकास खंडों में भू–जलस्तर में कोई गिरावट नहीं आई है। बांध खाली, रबी फसल भी होगी प्रभावित सामान्य से कम बारिश के कारण प्रदेशभर में बांध खाली पड़े हैं। ऐसे में रबी फसल प्रभावित होने की आशंका है। बरगी बांध की भंडारण क्षमता 3180 में से 2310 मिलियन घनमीटर भराव हुआ है। इंदिरा सागर की क्षमता 9750 है और भराव 3199 मिलियन घनमीटर है। ऐसे ही हालात दूसरी परियोजनाओं के भी हैं। हैंडपंप खराब, नलजल योजना बदहाल रू खराब हैंडपंप और बंद पड़ी नलजल योजनाओं को सुधारने की कोशिश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग दो साल से कर रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सौ करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद भी सुधार कार्य नहीं हुआ है, तो कई योजनाएं टेंडर की शर्तों के कारण उलझी हैं।

न्याय की नई बाधा

गुरुग्राम स्थित रायन इंटरनैशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न की जिस तरह हत्या हुई उससे हर किसी का सिहर उठना स्वाभाविक था। मगर सोहना बार असोसिएशन ने इस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उसे स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। बार असोसिएशन ने आनन–फानन यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि इस अमानवीय घटना के आरोपियों का मुकदमा कोई वकील नहीं लेगा। इसके बाद आरोपियों के लिए अपना पक्ष अदालत तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। इधर कुछ समय से वकीलों के बीच ऐसी प्रवृत्ति आम होती दिख रही है। जब भी कहीं कोई ऐसी घटना होती है जिससे समाज के बड़े हिस्से की भावना जुड़ी हो तो वकील समुदाय उस भावना में बहने लगता है। मुंबई आतंकी हमले के दोषी कसाब के मामले में ही नहीं, ऐसे कई मामलों में वकीलों का यह रुख दिखा। उससे पहले निठारी कांड में भी स्थानीय वकील ऐसा ही रवैया दिखा चुके थे। हाल के जेएनयू विवाद में तो वकीलों का एक समूह सड़क पर खुद ही इंसाफ करने पर आमादा हो गया था। कानून के रक्षक कहलाने वालों का ऐसा रुख देश की न्याय प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करता है। अच्छी बात यह हुई कि प्रद्युम्न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समय पर दखल दिया और ऐसे वकीलों को कड़ी फटकार लगाई। आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि बार असोसिएशन के हाथ खींच लेने से उन्हें वहां कोई वकील ही नहीं मिलेगा, इसलिए इस मामले को दिल्ली के किसी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। सोहना बार असोसिएशन को भी अदालत के गंभीर रुख का अंदाजा हो गया था इसलिए उसने सुनवाई शुरू होने से पहले ही वह प्रस्ताव वापस ले लिया। बावजूद इसके, कोर्ट ने यह स्पष्ट करने में कोई हिचक नहीं दिखाई कि बार असोसिएशन का यह रवैया नितांत गलत है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पक्ष के वकीलों की राह में किसी तरह की बाधा खड़ी हुई तो असोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा।

गांधी जी के सपनों का, स्वच्छ भारत बनाने के अभियान में जुटें

कहते हैं, जिस विचार का समय आ गया हो, उसे कोई रोक नहीं सकता! एक रक्तरंजित विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में, जब हिंसा ही युग की पहचान हुआ करती थी, भारत ने अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिये, सत्याग्रह के जरिये स्वतंत्रता हासिल की।

पूरा देश महात्मा के आह्वान के पीछे आ गया और अपनी स्वतंत्रता के रूप में भारत ने संसार के सामने एक मिसाल पेश कर दी। यह एक ऐसा विचार था, जिसका समय आ चुका था। उसी तरह आज, जब भारत का नाम खुले में शौच करने वालों की सबसे बड़ी तादाद के साथ इसके लिए बदनाम देशों की सूची में सबसे ऊपर है, 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण स्वच्छता प्राप्ति के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया स्वच्छ भारत का आह्वान एक ऐसा विचार है, जिसका समय आ गया है।

खुले में शौच जाने की परंपरा मानव सभ्यता के प्रारंभ जितनी ही पुरानी है। भारत के करोड़ों लोगों के लिए यह सदियों से जीवन शैली का हिस्सा है। 1980 के दशक से ही हमारे यहां सारी सरकारें राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम संचालित करती आ रही हैं, लेकिन 2014 तक केवल 39 प्रतिशत भारतीयों को ही शौच की सुरक्षित सुविधा उपलब्ध थी। कारण यह कि शौचालय तक लोगों की पहुंच होना कोई ढांचागत समस्या नहीं है। इस मामले में लोगों का व्यवहारगत रवैया और सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। 60 करोड़ों लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना एक ऐसी चुनौती है, जिसका सामना करने की अभी तक संसार में किसी ने कोशिश भी नहीं की है। यह उपलब्धि केवल एक सघन, समयबद्ध हस्तक्षेप के जरिये ही हासिल की जा सकती है, जिसका नेतृत्व सर्वोच्च स्तर से किया जा रहा हो, और जिसमें समाज व सरकार के सभी अंग मिल–जुल कर सक्रिय हों। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्रह ने राष्ट्र की कल्पना को ठीक उसी तरह आकृष्ट किया है, जिस तरह दशकों पहले महात्मा के सत्याग्रह ने किया होगा!

स्वच्छता के महत्व को दस्तावेजी रूप पहले ही दिया जा चुका है। इसके प्रभाव से डायरिया जैसी बीमारियों में आने वाली कमी बाल मृत्यु दर को नीचे लाती है। इससे स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी गरिमा सुनिश्चित होती है। स्वच्छता की कमी से होने वाला नुकसान उससे कहीं ज्यादा है, जितना यह ऊपर से नजर आता है। विश्व बैंक का एक अध्ययन बताता है कि मुख्यतरू स्वच्छता की कमी के चलते भारत के 40 फीसदी बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। हमारी भावी कार्यशक्ति का इतना बड़ा हिस्सा अपनी पूर्ण उत्पादक क्षमता ही हासिल न कर सके, यह हमारी मुख्य शक्ति, हमारे जनसंख्या बल के लिए एक गंभीर खतरा है। इस समस्या को सुलझाना आर्थिक महाशक्ति बनने से जुड़ी हमारी विकास कार्यसूची का आधार बिंदु होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का भी अनुमान है कि स्वच्छता के अभाव से भारत को उसकी जीडीपी के 6 फीसदी का नुकसान होता है।

यूनिसेफ के एक अध्ययन के मुताबिक खुले में शौच से मुक्त गांवों में हरेक परिवार ने साल में 50,000 रुपये बचाए। यह बचत दवाओं पर होने वाले खर्च में आई कमी तथा समय व जीवन बचने से हासिल हुई। इसके अलावा समुचित ठोस व द्रव कचरा प्रबंधन से अच्छी मात्रा में धन प्राप्ति की भी संभावना है। इसमें यह भी बताया गया है कि स्वच्छता से होने वाला प्रति परिवार आर्थिक लाभ 10 वर्षों के समेकित निवेश (सरकारी व अन्य स्रोतों द्वारा किए गए खर्च तथा परिवार द्वारा लगाए गए पैसे) का 4.7 गुना है। जाहिर है, स्वच्छता उम्मीद से ज्यादा फायदा देने वाला निवेश है। स्वच्छ भारत मिशन पर केंद्र व राज्य सरकारें पांच वर्षों में 20 अरब डॉलर खर्च करने वाली हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र, विकास एजेंसियों, ध ार्मिक संगठनों और नागरिकों की ओर से भी इसके लिए राशि आ रही है।

स्वच्छ भारत कोष द्वारा विशेष सफाई परियोजनाओं के लिए 660 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठा की गई और उसे जारी भी कर दिया गया। यह राशि लोगों के व्यक्तिगत योगदान और कंपनियों व संस्थानों की मदद से जुटाई गई। इसमें सबसे

ज्यादा 100 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत योगदान धार्मिक नेता माता अमृतानंदमयी का रहा। कई निजी कंपनियों ने अपने सीएसआर फंड से स्कूलों में सफाई की व्यवस्था की है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन में अब भी निजी क्षेत्र की रचनात्मकता और नवाचार के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अपने–अपने क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रमुखता देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वे इस पर एक निश्चित राशि खर्च करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वित्त वर्ष 2017–18 में यह राशि 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की होगी।

स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो तेजी से एक जनांदोलन का रूप लेता जा रहा है। खुले में शौच करने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। देश की 68 फीसदी से ज्यादा आबादी के पास अब सुरक्षित शौच की सुविधा उपलब्ध है।

खुले में शौच करने वाले अब 30 करोड़ से कुछ ही ज्यादा बचे हैं। मगर अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। इस मुहिम को और तेज करने के लिए सरकार 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान मंत्रियों, सांसदों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों से लेकर बड़ी–बड़ी हस्तियों, संगठनों, उद्योगपतियों, स्थानीय नेताओं और आम नागरिकों तक हर कोई श्रमदान के जरिए खुद को स्वच्छता के प्रति समर्पित करेगा। इस प्रकार सब मिलकर स्वच्छ भारत मिशन की संक्रामक ऊर्जा को और फैलाते जाएंगे। तो फिर सबके लिए एक मौका है। अपनी–अपनी आस्तीनें चढ़ाइए और गांधी जी के सपनों का भारत, स्वच्छ भारत बनाने के अभियान में जुट जाइए। आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ें और अपने हिस्से का कर्तव्य पूरा करें।

v#.k tsVyh
¼ys[kd dsUæh; foÙk ea=h gSa½

गोलीबारी के चलते सीमावर्ती गांवों के लोगों का हर दिन मुश्किलों भरा

जम्मू फ्रंटियर पर जीरो लाइन से सटे भारतीय सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों में से प्रत्येक की आज अपनी–अपनी दुखभरी दास्तान है। किसी की समस्या कुछ है तो किसी की कुछ लेकिन सभी की समस्याओं का निचोड़ यही निकलता है कि उसके लिए पाकिस्तान तथा उसके सैनिक दोषी हैं जिनके कारण इन लोगों को अनेकों संकटों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जो तब तक जारी रह सकते हैं जब तक सीमा का प्रश्न बरकरार है।

जम्मू फ्रंटियर की अंतरराष्ट्रीय सीमा के गांवों में समय के साथ–साथ समस्याओं का रूप भी बदलता जा रहा है। कुछेक अरसे में जहां पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा इस ओर घुसपैठ करके आम नागरिकों की पिटाई के मामलों में वृद्धि हुई है वहीं अपने पूर्वजों के मकान और खेत छोड़ शहरों की ओर स्थाई तौर पर पलायन करने की प्रवृत्ति ने भी जोर पकड़ा है। यही कारण है कि अधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि सीमा के साथ सटे शहरों की आबादी में वृद्धि होने लगी है जबकि सीमावर्ती गांवों में कई खेत और मकान अक्सर अब खाली नजर आने लगे हैं।

हीरानगर के लोंडी गांव के रहने वाले सुनील सिंह सीमा पर बने वातावरण से परेशान हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से इस माहौल ने उसे घर पर ही बांध रखा है और वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 60 किमी दूर कालेज में नहीं जा पाया है। रीगाल के रहने वाले जीत लाल की परेशानी यह है कि उसे अभी भी अपने खेतों में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि सीमा रेखा से सटे खेतों में जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है जबकि सामने पाक सैनिक मोर्चा जमाए बैठे हों। और सादे चक के रहने वाला बलजीत गत तीन महीनों से बिस्तर से ही बंधा है क्योंकि वह पाक रेंजरों की पिटाई का शिकार हुआ है। पढ़ाई का हर्जा, खेतों में कई दिनों तक न जा पाना, पलायन के लिए हमेशा ही तैयार रहना यह तो उन सभी गांवों में आम समस्या है या यूं कहा जाए कि उन लोगों की जिन्दगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है जो सीमा के साथ सटे गांवों में रहते हैं जो आजकल गर्माहट लिए हुए है। हजारों की तादाद में लोग इन गांवों में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की ओर से बढ़ते दबाव के कारण अब वे भी भयभीत होने लगे हैं जिसने अधि ाकारियों को भी चिंता में डाला है।

यह बात अलग है कि इन गांवों में सुविधाओं का हमेशा ही अभाव रहा है लेकिन सीमा पर बढ़ने वाले तनाव ने इसमें भी अपना भरपूर योगदान दिया है जिसके कारण उनमें और कमी आई है। अध्यापक, चिकित्सा सुविधाएं तो वैसे भी इन क्षेत्रों में नाममात्र की ही हैं लेकिन बावजूद इसके लोग किसी प्रकार दुखदर्द सहन कर अपना गुजारा कर ही रहे थे कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने एक कारण दिया है पलायन के लिए अपना बोरिया बिस्तर उठाने को। लेकिन इस संदर्भ में इसे याद रखना आवश्यक होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों द्वारा हमेशा ही उस समय पलायन का रास्ता अख्तियार किया जाता रहा है जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सीमावर्ती गांवों में लोग अच्छी स्थिति में न रहते हों बल्कि शहरों से अच्छे मकान और बंगलों का निर्माण किया जा चुका है। यही नहीं कई गांव जो जीरो लाइन से मात्र सात–आठ सौ मीटर की दूरी पर स्थित हैं और जब भी सीमा पर तनावपूर्ण माहौल होता है तो इन गांवों के उन लोगों को अपने घरों की चिंता सताने लगती है जिन्होंने कई–कई मंजिला कोठियों का निर्माण किया हुआ है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी आज सीमावासी किसी प्रकार अपने दिनों को काट रहे हैं। अधिकतर लोग सीमा पर उत्पन्न परिस्थितियों के लिए जहां तारबंदी को दोषी ठहराते हैं वहीं अब सीमा सुरक्षा बल को भी दोषी ठहराने लगे हैं, जिन पर आम लोगों का आरोप है कि वह पाकिस्तानी गोलीबारी का उत्तर उसी प्रकार देने से कतराती है जिस प्रकार पाकिस्तानी पक्ष करते हैं। लोग 'जैसे को तैसा' वाली स्थिति चाहते हैं ताकि सीमावर्ती गांवों से होने वाले पलायन को रोका जा सके।

जुमलों के सहारे ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकती सरकार

विपक्ष में बैठकर सरकार पर हमला बोलना काफी आसान होता है। मुझे याद है जब यूपीए के दौर में पेट्रोल–डीजल के दाम बढ़ते थे तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतर जाते थे...हर तरफ महंगाई का रोना रोया जाता था और सरकार को नए–नए तमगों से नवाजा जाता था। यहां तक कि खुद नरेंद्र मोदी भी सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूकते थे। आज देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए तक पहुंच गयी है लेकिन अच्छे दिन का नारा देने वाली सरकार खामोश है।

एक तरफ देश की जनता पेट्रोल–डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोदी कैबिनेट में शामिल उनके नए मंत्री केजे अल्फोंस की। मंत्री जी ने देश की जनता को अर्थशास्त्र समझाते हुए कहा कार और बाइक चलाने वाले ही पेट्रोल खरीदते हैं और पेट्रोल खरीदने वाले भूखे नहीं मर रहे।

मंत्री जी के बयान पर बीजेपी ने भले ही चुप्पी साध ली हो लेकिन शिवसेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना यहां तक बोल गई कि अच्छे दिनों की हत्या हो रही है और हम बीजेपी के साथ रहकर आरोपों के भागीदार नहीं बनेंगे। शिवसेना ने गठबंधन तोड़ने की धमकी भी दे डाली। सवाल उठता है कि जब कच्चे तेल के दाम करीब–करीब आधे हो गए तो पेट्रोल–डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे? आखिर ग्राहकों की जेब काटकर कौन कमाई कर रहा है? 26 मई 2014 को जब मोदी सरकार ने शपथ ली थी उस समय कच्चे तेल की कीमत 6330.65 रुपये प्रति बैरल थी। इस महीने कच्चे तेल की कीमत करीब–करीब आध ाी घटकर 3368.39 रुपये प्रति बैरल पर आ गई लेकिन फिर भी पेट्रोल–डीजल के दाम नहीं घटे। सरकार की ओर से तेल कंपनियों को पेट्रोल–डीजल के दाम तय करने की आजादी तो मिल गई लेकिन उसका ग्राहकों को फायदा नहीं हो रहा।1 जुलाई से पूरे देश में लागू नई टैक्स व्यवस्था जीएसटी से पेट्रोल–डीजर को बाहर रखा गया है और इन पर अब भी केंद्र और राज्यों के अलग–अलग टैक्स लग रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद से डीजल पर लागू एक्साइज ड्यूटी में 380 फीसदी और पेट्रोल पर 120 फीसदी का इजाफा हुआ है। इस दौरान केंद्र को इस मद से हुई कमाई भी तीन गुणा से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आम जनता की जेब अब भी कट रही है।

मोदी जी के मंत्री को कोई ये जाकर बताए कि दिल्ली में 15 हजार कमाने वाला शख्स भी बाइक रखता है...सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे शौक है..बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपने दफ्तर और फैक्ट्री जाने में ज्यादा किराया नहीं भरना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में दो किलोमीटर की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपए है, 2 से 5 किलोमीटर के लिए 15, 5 से 12 किलोमीटर के लिए 20, 12 से 21 किलोमीटर के लिए 30, 21 से 32 किलोमीटर के लिए 40 और 32 किलोमीटर से अधिक के सफर के लिए 50 रुपए।

एक नई बाइक 50 से 55 किलोमीटर की माइलेज देती है... अगर किसी का दफ्तर उसके घर से 12 किलोमीटर दूर है तो मंत्री जी खुद अंदाजा लगा लें कि उसके लिए क्या आसान होगा बाइक से ड्यूटी जाना या फिर मेट्रो को चुनना।

हाल के कुछ महीनों में सरकार के कामकाज का आकलन करने के बाद मुझे कहीं न कहीं इस बात का आभास होने लगा है कि बीजेपी फिर अपने पुराने ढर्रे पर जा रही है। याद कीजिए साल 2004 जब बीजेपी ने श्फील गुडश् और श्इंडिया शाइनिंगश् का नारा दिया था... बीजेपी को लगने लगा था कि जनता उसके साथ है लेकिन चुनाव में उसका ये नारा टायं–टायं फिस्स हो गया। सोशल मीडिया के जमाने में आप प्रचार से अपने पक्ष में कोई भी इमेज बना लें...लेकिन अगर जनता नाराज हो गई तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली में बड़े–बड़े फ्लाईओवर बनाने वाली शीला सरकार सिर्फ इसलिए सत्ता से बाहर हो गई थी क्योंकि जनता में यूपीए सरकार के खिलाफ गुस्सा था। कोई भी सरकार जुमलों के सहारे जनता को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकती।

euk t >k

¼yl[kd ,d Vhoh pkuy es ofj"B i=dkj gS½

क्या है ब्लू व्हेल चैलेंज? कैसे ले लेता है जान? कैसे बच सकते हैं इससे?

ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल चौलेंज का आतंक दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार इस पर रोक लगा चुकी है लेकिन इसके बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। दरअसल सरकार के आदेश के बावजूद इस गेम पर पूरी तरह रोक नहीं लगायी जा सकी है क्योंकि भले विभिन्न वेबसाइटों पर इस गेम से संबंधित यूआरएल ब्लॉक कर दिये गये हों लेकिन सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस गेम के लिंक यूजर्स तक पहुँच रहे हैं। इस गेम के बारे में दुनिया भर में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि यह डाउनलोड के लिए कम जगह ही उपलब्ध है और कम चर्चित साइटों पर ग्रुपों में इसके लिंक पोस्ट किये जाते हैं। ऐसे में इस गेम का खतरा धीरे–ध ीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ उपाय अपना कर हम बच्चों को इस गेम से दूर रख सकते हैं या फिर इस गेम के चक्कर में पड़ गये बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं।

[krjk dh ?kVh

यह गेम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब कोई इसे खेलने के लिए साइन–अप करता है तो शुरू में ही एडमिनिस्ट्रेटर कह देता है कि यदि एक बार इस खेल में एंटर कर लिया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। यस पर क्लिक करके ही यूजर आगे बढ़ पाता है और इसी दौरान उसे बता दिया जाता है कि खेल का अंत उसकी मौत से हो सकता है। यूजर इस बात का चौलेंज लेने को भी तैयार हो जाता है। गेम में आगे बढ़ने के लिए उसे अपना हर टास्क पूरा करने के बाद उससे संबंधित फोटो एडमिनिस्ट्रेटर को भेजना होता है तभी उसे अगले चरण में प्रवेश की अनुमति मिलती है। तो आप भी यदि किसी बच्चे को अचानक से अत्यंत गंभीर होते देखें और आपको लगे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है तो सतर्क हो जाना चाहिए।

,sls c<rk gS [ksy vkxs

इस गेम में यूजर को अलग–अलग मोबाइल नंबरों से टास्क भेजे जाते हैं और कई बार टास्क को लाइव भी करके दिखाना होता है। हर टास्क पूरा होने पर बधाई संदेश भी आता है।

एक बार कोई इस गेम में घुस गया तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस पर पहले भावनात्मक दबाव बनाया जाता है और बाद में उसे डराया धमकाया जाता है और टास्क पूरा नहीं करने पर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही जाती है। इस गेम के जाल में ज्यादातर अकेलापन महसूस करने वाले या भावुक लोग ही आसानी से फंस रहे हैं। टास्क के तहत कई बार हॉरर मूवी दिखायी जाती हैं और उस समय यूजर के चेहरे के भाव पढ़कर एडमिनिस्ट्रेटर उसके अगले टास्क के बारे में फैसला करता है। यूजर के मन में हर टास्क को पूरा करने और अगले चरण में पहुंचने का जुनून पैदा कर दिया जाता है और इस चक्कर में उसकी रातों की नींद भी गायब हो जाती है।

,sls cjrsa lko/kkuh

यदि कोई बच्चा अभिभावकों से छिप कर मोबाइल फोन या टैबलेट का उपयोग कर रहा है तो उस पर सावधानी से नजर रखने की जरूरत है क्योंकि ब्लू व्हेल चौलेंज के ज्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि बच्चे छिप–छिप कर यह गेम खेलते हैं। ऐसे बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे बच्चों को डांटने या मारने से स्थिति बिगड़ सकती है इसलिए या तो उसे प्यार से समझायें या फिर किसी अच्छे काउंसलर से उसकी काउंसिलिंग करवाएं। इस गेम की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें चरण दर चरण अपने आप को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। इस गेम में जो टास्क दिये जाते हैं उससे ही आपको इसके खतरनाक स्तर का अंदाजा लग जायेगा। बानगी देखिये–

–हाथ पर रेजर से कोई नंबर लिखने को कहा जाता है।

–रोज सुबह 4.20 पर उठने और हॉरर फिल्में देखने के लिए कहा जाता है।

–ब्लू व्हेल खेलने के लिए पैरों पर येस लिखने को कहा जाता है।

–सोशल मीडिया स्टेटस में व्हेल लिखने या व्हेल की फोटो लगाने के लिए कहा जाता है।

–छत की मुंडेर से बाहर की तरफ पैर लटका कर बैठने के लिए कहा जाता है।

–सुबह 4.20 पर उठ कर रेलवे लाइन के पास जाने के लिए कहा जाता है।

dgka ls gqvk bl [ksy dk tUe

जहां तक इस खेल के जन्म की बात है तो श्ब्लू व्हेल गेमश या श्द ब्लू व्हेल चौलेंजश नाम का गेम रूस के फिलिप बुडेकिन नाम के शख्स ने 2013 में बनाया था। इस खेल में एक एडमिन होता है, जो खेलने वाले को अगले 50 दिन तक बताते रहता है कि उसे आगे क्या करना है। इस खेल के आखिरी दिन खेलने वाले को आत्महत्या करनी होती है और उससे पहले एक सेल्फी लेकर अपलोड करनी होती है।

& 'kHkk nRr

राहुल को समझना होगा पूरा भारत खानदान पर नहीं चलता है

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गलत कहा है कि पूरा भारत खानदानों पर चलता है। शासन करने का मतलब है केंद्र में सत्ता संभालना। ऐसा करने का अवसर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के परिवार को मिला है। नेहरू ने 17 साल शासन किया, उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने 18 साल तथा उनके पुत्र राजीव गांधी ने पांच साल। इस तरह, यह खानदान केंद्र में 40 साल तक सत्ता में रहा जो अगस्त 1947 में आजादी मिलने के बाद की अवधि का आधे से भी ज्यादा है।

नेहरू ने यह पक्का किया कि उनकी बेटी शासन करेगी, अगर उनके शासन के तुरंत बाद नहीं तो कुछ समय बाद। मैं जब लाल बहादुर शास्त्री के साथ सूचना अधिकारी के रूप में काम कर रहा था और उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए तैयारी करने को कहता था, खासकर उस समय जब नेहरू को हृदयाघात आया था, तो शास्त्री कहते थे, श्श्उनके मन में तो उनकी सुपुत्री हैश्श और इसके साथ यह भी जोड़ते थे कि यह आसान नहीं होगा। वह पंडित जी को चुनौती नहीं देंगे और इलाहाबाद लौट जाएंगे। लेकिन मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे।

नेहरू के मरने के बाद यही हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज नेहरू के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने एक चाभी ढूंढ़ निकाली जिससे कई ताले खुलते थे। दक्षिण से संजीव रेड्डी, कलकत्ता से अतुल्य घोष तथा बबंई से एसके पाटील अपने ही अधिकार से दिग्गज थे, लेकिन वे शास्त्री को स्वीकार करने के लिए तैयार थे क्योंकि वह उन लोगों को यह महसूस नहीं होने देते थे कि वे उनके बराबर नहीं हैं।

मैं इंडियन एक्सप्रेस में राजनीतिक संवाददाता के रूप में काम करता था। उस समय मैंने लिखा था, श्श्सन् 1963 की गर्मियों में एक खामोशी भरी रात पांच लोग दक्षिण के प्रसिद्ध तीर्थस्थल तिरूपति की फैली हुई घाटी को निहारते एक सुनसान बगंले को ढूंढते हुए पहुंचे। एक बेढंगा और भारी भरकम था, दूसरे बड़े डील. डौल वाला, तीसरा फुर्तीला और तेज, चौथा कम लंबाई का और पांचवां एक मांसल कुश्तीबाज की तरह था। पांचों अलग.अलग दिशाओं से आए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, और ऐसा करने में वे सफल रहे। सड़क पर शायद ही कोई नजर आ रहा था। ज्यादातर लोग जल्द ही सो गए थे ताकि सुबह होने के पहले मंदिर पहुंच सकें। शास्त्री के मरने के बाद सत्ता खानदान के पास लौट आई।

लेकिन राहुल गांधी असहिष्णुता का माहौल पैदा करने के लिए प्रध ानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं तो सही करते हैं। सत्रह करोड़ की संख्या वाले मुसलमानों की कहीं कोई गिनती नहीं है। उन्होंने लोगों की नजर से भी अपने को दूर कर लिया है। ऐसा है मानो उन्होंने अपने ही देश में दूसरी श्रेणी के नागरिक की हैसियत को स्वीकार कर लिया है।

दूसरी ओर, कुल मिलाकर हिंदुओं ने उन्हें विभाजन के लिए माफ नहीं किया है। आज भी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है तो मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। वैसे भी, उन्हें उन बस्तियों, जो झोपड़ पट्टियां हैं, में खुद अपनी देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। रोजगार में उनकी गिनती उंगलियों पर हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत थोड़े सफल होते हैं। सच्चर कमिटी ने सामने लाया है कि किस तरह उनकी हालत दलितों से बदतर है।

हिंदुओं को उन्हें गरीबी के ढेर से बाहर निकालना है। लेकिन उन्हें लाचारी के कीचड़ में पड़े रहने को छोड़ दिया गया है। धर्म के नाम पर बंटवारे ने एक ऐसी लाइन खींच दी जिसके कारण मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है और फिर भी वे धार्मिक पूर्वाग्रहों के पक्ष में हैं। मिली.जुली कालोनियां भी गायब हो रही हैं और मुसलमान अपने समुदाय के बीच ही सुरक्षित महसूस करते हैं जब जगह एकदम रहने लायक नहीं होती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में दो समुदायों के बीच खाई बढ़ रही है। आरएसएस के लोग यह ध्यान रखते हैं कि कोई मुसलमान सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर न हो। मुझे याद है कि एक मुसलमान इंजीनियर जिसने मुझे श्रीनगर हवाई अड्डे छोड़ा था, ने शिकायत की कि एक नौकरी की तलाश में वह बैंगलुरू गया था, लेकिन जब पहचान.पत्र देखा गया तो उसे सीधे खारिज कर दिया गया।पाकिस्तान के संस्थापक कायद.ए.आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था कि दोनों देश. एक हिंदु बहुमत वाला, दूसरा मुस्लिम बहुमत वाला, अपना कामकाज इस तरह चलाएंगे कि राज्य के मामलों के बीच धर्म नहीं आएगा। यह दुख की बात है कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। नहीं तो, इसने देश को सेकुलर मंच दिया होता। राहुल गांधी धीरे. धीरे समझेंगे कि उनकी पार्टी को फिर से जमीन पर काम करना पड़ेगा और लोगों के स्वभाव के बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। भारत ने एक लोकतांत्रिक और सेकुलर देश बनाने की लड़ाई लड़ी थी और महात्मा गांधी तथा जवाहर लाल नेहरू, दोनों ने लोगों को अपनी विरासत की याद दिलाई थी जिसके वारिस हिंदु और मुसलमान दोनों हैं।

वास्तव में, यह अचरज की बात है कि नेहरू के नाम को मिटाने की कोशिश हो रही है। उदारवादी अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के उत्साही समर्थक थे। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं, उस समय सांसद था, उनसे मिलने उनके कमरे में गया। वाजपेयी ने बहुत गर्व से कहा कि वह उसी कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर एक समय नेहरू बैठते थे। लेकिन आज भाजपा नेहरू मेमोरियल सेंटर से नेहरू का नाम हटाने की कोशिश कर रही है। कुछ विद्वान इस प्रयास को रोकने की कोशिश में हैं, लेकिन मामला प्रधानमंत्री कार्यालय के पास छोड़ा हुआ है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि नेहरू उन दिग्गजों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन देश की आजादी के लिए उनका सकंल्प थोड़ा भी कम नहीं हुआ। राहुल गांधी को उनके नक्शे.कदम पर चलना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, खानदान की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र और सेकुलर मूल्यों के लिए। भारत के लोग कांग्रेस को फिर से प्रासंगिक बना देंगे। महत्वपूर्ण चीज है विरासत एक, लोकतांत्रिक और सेकुलर।

& dyhi uk;j

झिझकें नहीं, बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताएं

आजकल विभिन्न स्कूलों में बच्चों के साथ यौन शोषण की खबरें आम हो गयी हैं। तमाम कड़े से कड़े कानून मौजूद होने के बावजूद लोगों के मन में लगता है भय रह ही नहीं गया है। युवतियों और महिलाओं पर ही भड़काऊ कपड़े पहनने का आरोप लगा देने वालों को इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि चार–पांच साल की बच्चियां स्कूल ड्रेस में कहां से भड़काऊ लगती हैं कि उन्हें भी नहीं बख्शा जाता है।

dju gkx mik;

–अकसर हम टीवी देखते समय किसी प्रकार के अंतरंग दृश्य आने पर या फिर यौन शोषण के दृश्य आने पर टीवी बंद कर देते हैं या फिर बच्चों को इधर उधर भेज देते हैं। ऐसा करने की बजाय हमें उन्हें वह देखने देना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें यह बात आसानी से समझ आती है कि गुड टच और बैड टच में क्या अंतर होता है।

–यदि यौन शोषण से जुड़े किसी केस को टीवी पर दिखाया जा रहा है तो उसे भी बच्चे को देखने दे सकते हैं ताकि बच्चा यह समझ सके कि ऐसी परिस्थिति में खुद को कैसे बचाना है या कैसे मदद हासिल करनी है।

–अपने बच्चे के दोस्त बन कर रहें। यदि आप उन्हें डांटते फटकारते ही रहेंगे तो वह कभी आपको अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे। बच्चों से स्कूल के सहपाठियों, टीचर या स्टाफ आदि के बारे में जानकारी लेते रहें।

–अक्सर स्कूल कार्यदिवसों के समय में अभिभावकों को स्कूल परिसर के अंदर नहीं आने देते हैं इसलिए अगली बार जब भी पीटीएम में जाएं तो स्कूल के प्रवेश द्वार से लेकर बच्चे की कक्षा तक के रास्तों का खुद मुआयना करें और देखें कि सभी जगह सुरक्षित हैं या नहीं।

–आप स्कूल बस में आने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों की पहचान सत्यापित कराई गई है या नहीं इस बारे में स्कूल से जानकारी ले सकते हैं।

–स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरा हैं या नहीं और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं इस बारे में भी स्कूल से जानकारी हासिल कर सकते हैं।

–अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल में है या नर्सरी में है तो यह देख लें कि स्कूल में उनके लिए अलग से वॉशरूम है या नहीं।

–बच्चे को अकेले बैठा कर बातें समझाने से अच्छा है कि काम करते करते समय समय पर उसे सीख देते रहें जैसे उसे नहलाते समय यह बता सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट को किसी को नहीं छूने देते हैं या ना ही किसी को दिखाते हैं।

सम्पादक : विनोद चन्द्र पनेरू

स्वामी प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक **विनोद चन्द्र पनेरू** द्वारा भीड़ापानी–ओखलकाण्डा, प्रिंटिंग प्रेस, भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित तथा तल्ली बमौरी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड से प्रकाशित। प्रकाशित खबरों के लिए प्रेस उत्तरदायी नहीं है। मो.– **9410354318** E-mail:- vinodpaneru123@gmail.com

एप से क्राप कटिंग का निरीक्षण

हवालबाग के ग्राम पंचायत पंचगांव पहुंची जिलाधिकारी इवा श्रीवास्तव

xkeh.kk us txyh tkuojk l gk jg udlku dh leL;k, crkb

vYekMkA प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सीसीई एडी ऐप के माध्यम से क्राप कटिंग का निरीक्षण जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने आज विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम पंचायत पंचगांव में तीन किलोमीटर पैदल चलकर किया।

उन्होने कहा कि जनपद में कुल 193 गांव का चयन क्रॅाप कटिंग के लिए किया गया है जिसमें धान की खेती हेतु 99 गांव एवं मंडुवा की खेती के लिए 94 गांव चयनित किये गये हैं। हवालबाग विकासखण्ड में ऐसे 10 गांवों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पंचगांव में दर्शन सिंह एवं मोहन सिंह के खेतों में क्राप कटिंग का जायजा लिया। इसके बाद जिलाधिकारी ने धान की मड़ाई अपने सम्मुख करायी। इस खेत में अप्रैल में धान की बुआई की गयी थी काश्तकार महिला आशा देवी व पूजा नेगी ने बताया

कि इस धान की खेती हेतु पानी की आवश्यकता अधिक होती है इस वर्ष वर्षा अधिक होने से अन्य वर्षो की अपेक्षा फसल ठीक है। उन्होने जिलाधिकारी को बताया कि फसल को जंगली सुअरों द्वारा नुकसान पंहुचाया जाता है।

इस पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जंगली सुअरों के नुकसान से बचाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनायी जाएगी। उन्होने वहां पर ग्रामीणों की अन्य समस्याओं का जायजा लिया वहां पर पीने की पानी की समस्या ग्राम प्रधान सुन्दर लाल ने रखी। जिलाधिकारी ने कहा कि यहां पर जल– संरक्षण एवं जल–संवर्धन का कार्य मनरेगा के तहत करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि इसी तरह जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों मे जाकर इस योजना का जायजा लिया जायेगा इसके लिए कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। इस अवसर पर अपर संख्याधिकारी मण्डलीय कार्यालय डा0 डी0 के0 काण्डपाल ने विस्तृत रूप से इस योजना के बारे में बताया। इस दौरान तहसीलदार खुशबु आर्या, अपर संख्याधिकारी बिशन सिंह कोरंगा, सहायक संख्याधिकारी मीना नेगी, पटवारी हवालबाग राजेन्द्र गिरी गोस्वामी, ग्रामीण मोहन सिंह नेगी, दर्शन सिंह आदि उपस्थित थे।

fu'kqYd ;k=k dk mBk, ykHk% ftykf/kdkjh

vYekMk। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि समस्त उपजिलाधिकारियों व सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड परिवहन अल्मोड़ा को निर्देश दिये है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं दिवगंत हुये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवावों को एक सहायक जिलाधिकारीध्अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत उनके परिचय पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वल्बो बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा यह निर्देश प्रबन्धन निदेशक परिवहन निगम देहरादून को दिये गये है। जिलाधिकारी समस्त उपजिलाधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिये है।

छात्र–छात्राओं को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाई

गांधी पार्क से जिला पंचायत कार्यालय तक जागरूकता रैली निकाली

xk"Bh d nkjku lQkb dk egRo crk;k

:æijA सोशल एण्ड हैल्थ एवरनेस सोसाइटी (सहस), जिला प्रशासन व नगर निगम के सहयोग से 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2017 तक चल रहे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगो को जागरूक करने के उदे्श्य से आज गांधी पार्क से जिला पंचायत कार्यालय तक जागरूकता रैली निकाली गई जिसमे जनपद के विभिन्न विद्यालय के छात्र–छात्राओ द्वारा प्रतिभाग किया गया। जागरूकता रैली समापन के बाद अपर जिलाधिकारी प्रताप सिंह शाह द्वारा जिला पंचायत सभागार मे स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाई गई।

मुख्य अतिथि के रूप मे बोलते हुए सुरेश गंगवार ने कहा सहस संस्था द्वारा लोगो को जागरूक करने के उदे्श्य से यह अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होने कहा 02 अक्टूबर को जनपद की 391 ग्राम सभाओ

मे स्वच्छता कार्यक्रम चलाये जायेंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सहस संस्था व जिला पंचायत राज कार्यलय का सहयोग लिया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी प्रताप सिंह शाह ने कहा सरकार द्वारा 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा एवं 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडा कार्यक्रम चलाये जा रहे है। उन्होने कहा हमे इस अवधि तक ही सीमित न रहकर सफाई को अपनी आदतो मे सुमार कर हमेशा सफाई के प्रति जागरूक रहना है।

उन्होने कहा हम सभी अपने घर व आस–पास को साफ–सुथरा रखे। उन्होने कहा कोई भी कार्य छोटा या बडा नही होता है इसलिए जनपद के प्रत्येक नागरिक को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ वातावरण से ही निरोग रहते हुए स्वच्छ तन व मन का निर्माण होता है।

संस्था के कुलीन गुप्ता ने कहा स्वच्छता एक ऐसा अभियान है जो सबकी जिम्मेदारी है। उन्होने कहा संस्था के माध्यम से लोगो को जागरूक करने के लिए समय–समय पर ऐसे अभियान चलाये जायेंगे।

कार्यक्रम मे सफाई कर्मचारी यूनियन, सिडकुल के अजय तिवारी, सिडकुल एसोशिएशन के मनोज तिवारी व उनकी टीम, बार एशोसिएशन के राजेन्द्र चन्द्र, इंडियन मेडिकल एशोसिएशन के रवि फुटेला, चार्टेड एकाउंट यूनियन के कपिल अरोरा, देवभूमि व्यापार मण्डल के विजय फुटेला व हरविंदर सिंह, ग्राम प्रधान संघ के विकास शर्मा, पेंशनर्स एसोशिएसन के राज बहादुर व उनकी टीम, समाज सेवी सुरजीत सिंह ग्रोवर, समीर अहमद, लक्की खरबंदा, किसान नेता राजीव चौधरी, महेंद्रा एण्ड महेन्द्रा के अतुल, डाबर के अवनेश यादव, टाटा के आशुतोष, बिसलेरी के विकास पांडे, पारले के संदीप पांडे, जिला सूचना अधिकारी बीसी तिवारी, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के भरत

शाह, एनश्योरेंस कंपनी के श्रीकर सिन्हा, डीपीएस के सुरजीत ग्रोवर आदि लोगो को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन घनश्याम गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम मे सीओ स्वतंत्र कुमार सिंह, जीएस जैन, डीके आर्य, सीबी घिल्डियाल, संदीप कुमार आदि उपस्थित थे।